

शिक्षकों की भूमिका का नये सिरे से मूल्यांकन होना चाहिये।

शिक्षक—दिवस को सिर्फ औपचारिकता न समझें।

— हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

5 सितंबर के दिन देश के लाखों स्थानों पर स्कूलों, कालेजों एवं यूनिवर्सिटियों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। किन्तु डा. राधाकृष्णन की कल्पना के अनुरूप क्या आज भी समाज में शिक्षक और शिक्षा के पेशे को हम वह सम्मान दे पाये हैं, जो उसे मिलना चाहिये? हम इंजीनियरों, डाक्टरों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आईएएस, आईपीएस, नेताओं, उद्योगपतियों, साधु—सन्तों और फिल्मी अभिनेताओं से मिलकर जितना गद्गद् होते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं, क्या ऐसा हम तब भी महसूस करते हैं जब अपने किसी पुराने शिक्षक से मिलते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था अभी हाल ही में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर दुनिया में 6वें नंबर पर पहुंच गई। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरे स्थान पर भी पहुंचने के लिये उम्मीद रखते हैं। किन्तु क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े गुणात्मक परिवर्तनों और सुधारों के बिना यह संभव होगा? चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे दरवाजे खटखटा रही है, किन्तु हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली अभी भी 18वीं सदी में हुई प्रथम औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए रोजगार के ढांचे के अनुरूप कवायद कर रही है।

दरअसल पिछले एक दशक में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे युगान्तरकारी परिवर्तन आये हैं कि विश्वस्तर पर उद्योगों, व्यवसायों, बाजारों, समाज, शिक्षा, मीडिया और राजनीति में सब कुछ उलट—पलट रहा है। यह 'सब कुछ' इतनी तेजी से घटित हो रहा है कि कभी—कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कोई वैज्ञानिक उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं या कोई हॉलीवुड की एवेंजर जैसी फिल्म देख रहे हैं। सूचना क्रांति ने दुनिया को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, किन्तु चौथी औद्योगिक क्रांति ऐसे बड़े बदलाव लाने जा रही है जिनकी कोई कल्पना नहीं कर पायेगा।

आज शिक्षक दिवस पर गहराई से सभी को यह सोचना है कि क्या हमारे स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय इस चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में सजग और जागरूक हैं या अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सोये हुए पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं? क्या हमारे राजनेता, नीति निर्माता, शिक्षक और विद्यार्थी इस कटु सत्य से वाकिफ है कि वर्ष 2030 तक, आजकल मिलने वाले अधिकांश रोजगार खत्म हो जायेंगे और जो नये रोजगार मिलेंगे उनकी तैयारी के लिये आवश्यक शिक्षा, पाठ्यक्रम, उपकरण, शिक्षक और पढ़ाने के तौर-तरीके हमारे पास नहीं हैं।

दरअसल आज दुनिया में चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुरूप 'शिक्षा 4.0' की बहुत चर्चा हो रही है जिसे मोटे तौर पर चौथी शैक्षणिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। वर्ष 2030 तक पहुंचते-पहुंचते दुनिया में शिक्षक का पेशा खत्म नहीं होने जा रहा है किन्तु एक बात तय है कि शिक्षक की महन्ता और भूमिका में बड़े बदलाव आयेंगे। शायद शिक्षकों को डाक्टरों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अभिनेताओं और राजनेताओं से ज्यादा महत्व और सम्मान मिल पायेगा। सबसे बड़ा बदलाव होगा कि शिक्षक का काम सिर्फ व्याख्यान देकर ज्ञान बांटना न हो कर, युवा-पीढ़ी को एक कोच, मेंटर या मित्र के रूप में भविष्य का रास्ता दिखाने का होगा।

शिक्षक-दिवस को एक उत्सवधर्मी औपचारिकता न समझते हुए आज यह सोचने की जरूरत है कि शिक्षक होने के क्या मायने और सरोकार होते हैं? शिक्षक-दिवस पर हमें आज यह आत्म-विश्लेषण करना होगा कि जिस भारतीय समाज में 20वीं सदी में सर आशुतोष मुकर्जी, डा एस राधाकृष्णन, प्रा. वीएस झा, प्रो केएन राज, प्रो पीसी महलनोबिस, डा रामास्वामी मुदालियर, डा वीकेआरवी राव और प्रो डीटी लकडावाला जैसे शिक्षकों की पूजा होती थी, परन्तु आज हमारी युवा पीढ़ी क्रिकेट, फिल्म और टी.वी. के कलाकारों, एथलीटों और उद्यमियों को ही अपना आदर्श क्यों समझने लगी है।

शिक्षकों के बारे में समाज की धारणा पिछले 65 वर्षों में कैसे बदल गयी, यह हमारे साहित्य और फिल्मों में शिक्षक पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी देखा जा सकता है। 20वीं सदी के लेखकों यथा प्रेमचन्द, शरत चंद्र, बंकिम चन्द्र, रवीन्द्र नाथ टैगोर आदि ने अपनी रचनाओं में शिक्षकों को बहुत सकारात्मक रूप में चित्रित किया था। भारतीय फिल्मों में आजादी से पहले और बाद के कालखण्डों में शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता और एक आदर्श नायक के रूप में दिखाते रहे। फिल्म गंगा-जमुना में जब अभिनेता अभि भट्टाचार्य को "इंसाफ की डगर पे, बच्चो दिखाओ चल के" गाना स्कूली बच्चों के साथ गाता हुआ दिखाया गया तो भारतीय युवाओं को एक बहुत मूल्यवान संदेश मिला।

पिछले दशक की फिल्मों में शिक्षकों को एक हास्यास्पद चरित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इन फिल्मों में शिक्षक की भूमिका हंसी पैदा करने के लिये है क्योंकि वे एक सनकी, जिद्दी और तानाशाह के रूप से कहानी में प्रवेश करते हैं और विद्यार्थी-वर्ग की मानसिकता से बिल्कुल कटे हुए हैं। बॉलीवुड की फिल्मों 'श्री इंडियटस' और "मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस." में प्रिंसीपल को निश्चित रूप से एक नकारात्मक चरित्र के रूप में पेश किया गया था।

आजादी के बाद भारतीय समाज ज्ञान, विद्या, समानता, चरित्र निर्माण, भाईचारा, सद्भाव और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा लगातार खोता गया है। इसके विपरीत भ्रष्टाचार, धनलिप्सा, स्वार्थपरिता, चालाकी और अवसरवादिता जैसे नकारात्मक मूल्य हमारे लोकतांत्रिक समाज पर हावी होते चले गये। इस दौर में शिक्षकों की पेशागत प्रतिबद्धताओं और योग्यताओं में भी लगातार क्षरण होते देखा गया। आजादी के बाद के प्रारंभिक दशकों में शिक्षकों की कार्यदशाएं और वेतन-भत्ते अन्य पेशों की तुलना में कम थे। नतीजतन पूरे देश में प्राथमिक, स्कूली एवं कालेज-यूनिवर्सिटी शिक्षकों की यूनियनों ने शिक्षकों को लामबन्द करके लगातार आन्दोलन किये। शिक्षकों को राजनैतिक दलों ने

विधायिकाओं एवं संसद के लिये भी नामित किया गया और उन्हें चुनाव लड़ने की छूट भी दी गई। शिक्षक संघों के आंदोलनों से जहां उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया वहीं दूसरी ओर उन्हें शिक्षा के उन्नयन से लगातार विमुख होते भी देखा गया। क्या स्कूल, कालेज तथा यूनिवर्सिटियों के शिक्षकों से जुड़े हुए राष्ट्रीय व प्रादेशिक संघ शिक्षकों की इस उदासीनता के लिये उत्तरदायी नहीं?

पिछले 3 दशकों में चौथे वेतन आयोग से लेकर छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों की तरह शिक्षकों के वेतनमानों में लगातार वृद्धि होती गई। मिसाल के तौर पर 1977 में डिग्री कालेज के लैक्चरर को करीब एक हजार रु मासिक वेतन मिलता था, जो छठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लगभग रु. 45000 तक पहुंच गया है यानी कि 41 वर्षों में 45 गुना। भारतीय समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा में गिरावट का कारण शिक्षकों के आर्थिक स्तर में सुधार के साथ-साथ उनकी पेशागत प्रतिबद्धता में कमी होना भी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में डिग्री कालेजों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में 100 दिन भी पढ़ाई नहीं होती है। इसके लिये शिक्षकों से ज्यादा जिम्मेदारी कुलपतियों, प्राचार्यों एवं विभागाध्यक्षों की है जो अनुशासनहीनता के विरुद्ध कदम उठाने का खतरा नहीं उठाते।

यह भी सच है कि सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं। शिक्षकों के एक बड़े वर्ग की दिलचस्पी पढ़ाने-लिखाने में रहती है। हमारे देश में उच्चशिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तादाद अभी हाल में 3.54 करोड़ बताई जाती है। इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये जरूरी समुचित संसाधनों की कमी लगातार देखी गई है। उच्चशिक्षा संस्थानों में कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, लायब्रेरी, होस्टल, स्पोर्ट्स आदि की सुविधाएं पर्याप्त और अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं।

देश के किसी भी कालेज या यूनिवर्सिटी कैम्पस में अगर आप जायें, तो युवा विद्यार्थियों का अक्सर हुजूम दिखाई देगा। आम तौर पर इसका कारण कक्षाएं न

लगना होता है। लेकिन इस भीड़-भाड़ का एक मुख्य कारण युवा आबादी में हो रही बेतहाशा वृद्धि के साथ-साथ उच्चशिक्षा का समुचित विस्तार न होना है। कल्पना करिये कि वर्ष 2025 तक उच्चशिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जब मौजूदा 3.54 करोड़ से बढ़कर 5.4 करोड़ हो जायेगी, तो कैसा परिदृश्य होगा? विश्व के अन्य विकसित व विकासशील देशों की तुलना में हमारे पास कम शिक्षक उपलब्ध हैं। मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट (2013) के अनुसार इस समय देश में करीब 12 लाख शिक्षक कालेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों में 40 प्रतिशत तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 35 प्रतिशत शिक्षकों की जगहें खाली पड़ी हुई है।

शिक्षक-दिवस के दिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारी शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ जितनी विराट हैं, उनका पुख्ता समाधान सरकार, शिक्षक और समाज के संयुक्त एवं दीर्घकालीन प्रयासों द्वारा ही संभव है। आज जो चुनौतियाँ भारतीय शिक्षा में दिख रही हैं, उनके बीज '60 और '70 के दशकों में बोये गये थे। जाहिर है कि भारतीय समाज और सरकार को शिक्षकों की भूमिका का नये सिरे से मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों में भी आत्मालोचना की बड़ी जरूरत है। उन्हें नयी शिक्षण पद्धतियों, सूचना प्रौद्योगिकी, चौथी औद्योगिक क्रांति एवं 21वीं सदी के शिक्षाशास्त्र से प्रशिक्षित और सुसज्जित करने की जरूरत है।

यह कार्य कितना कठिन है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7वें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार सन् 2002 में हमारे स्कूलों में 55.30 लाख शिक्षक कार्यरत थे। इनकी कुल संख्या अब करीब 80 लाख होनी चाहिये। इसमें अगर 12 लाख कालेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों की संख्या को जोड़ दिया जाये, तो देश में शिक्षकों की कुल संख्या 92 लाख हो जायेगी। क्या हम भारतीय समाज में उनको एक सम्मान जनक स्थान देने की स्थिति में हैं और

क्या 21वीं सदी के ज्ञानोन्मुख समाज के लिये हम उन्हें नये सिरे से प्रशिक्षित और प्रेरित कर पायेंगे?